

चसाचारस

EXTRAORDINARY

भाग I---सण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74]

नई विस्ली, दानिबार, ग्राप्रैल 25, 1970/वैशाल 5, 1892

No. 741

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25, 1970/VAISAKHA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पूळ संख्या दी जाती है जिससे कि यह द्यलग संकलन के रूप में रक्ता जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd April 1970

No. F.7(25)-E.III(A)/69.—The Government of India have decided to set up a Pay Commission composed of the following:—

Chairman

(1) Shri Raghubar Dayal, ex-Judge of the Supreme Court.

Members

- (2) Dr. Nihar Ranjan Ray,
- (3) Prof. A. K. Das Gupta.
- (4) Dr. V. R. Pillei.

Member-Secretary

- (5) Shri H. N. Ray. ICS.
- 2. The Commission will be required to enquire into and make recommendations on:—
 - (i) the principles which should govern the structure of emoluments and conditions of service of Central Government employees;

- (ii) what changes in the structure of emoluments and conditions of service of different classes of Central Government employees are desirable and feasible:
- (iii) death-cum-retirement benefits of Central Government employees;
- (iv) the structure of emoluments and conditions of service, including deathcum-retirement benefits, of personnel belonging to the All India Services;
- (v) the structure of emoluments including benefits in cash and kind and death-cum-retirement benefits of personnel belonging to the Armed Forces, having regard to their terms and conditions of service;
- (vi) the structure of emoluments and conditions of service, including deathcum-retirement benefits, of employees of the Union Territories: and
- (vii) while enquiring into the level of minimum remuneration, the Commission may examine the Central Government employees' demand for a need-based minimum wage having regard to all relevant factors.
- 3. The Commission will make its recommendations having regard, among other relevant factors, to the economic conditions in the country, the resources of the Central Government and the demands thereon such as those on account of developmental planning, defence and national security, the repercussions on the finances of the State Governments, public sector undertakings, local bodies, etc.
- 4. In case, in view of the increase in cost of living, the need for consideration of relief of an interim character arises during the course of deliberations of the Commission, the Commission may consider the demand for relief of an interim character and send reports thereon. In the event of the Commission recommending any interim relief, the date from which this relief should take effect will be indicated by the Commission.
- 5. The Commission will devise its own procedure and may appoint such advisers as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission. The Government of India trust that the State Governments, service associations and others concerned will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance.
 - 6. The Commission will make its recommendations as soon as practicable,

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

P. GOVINDAN NAIR, Secy.

वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मंत्रैल 1970

सं॰ एफ॰ 7(25)-ई 111(ए)/69--भारत सरकार ने एक वेतन श्रायोग नियुक्त करने का निर्णय किया है जिसका गठन निम्निखित प्रकार से किया जायगा:---

ग्रध्यक्ष

(1) श्री रघुवर दयाल, सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश।

सदस्य

- (2) बा॰ निहार रंजन राय।
- (3) प्रो० ए० के० दास गुप्त।
- (4) डा० वी० ग्रार० पिल्सी।

सदस्य सिचव

- (5) श्री एच० एन० राय, ग्राई० सी० एस०।
- भायोग को निम्नलिखित बातों की जांच करनी होगी भौर उन पर भपनी सिफारिशें वेनी होंगी:—
 - (i) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बेतन के ढांचे और सेवा की शर्तों के नियामक सिक्कान्त।
 - (ii) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भिन-भिन श्रेणियों के वेतन के ढांचे भीर सेवा की शर्तों में कौन से परिवर्तन वांछनीय तथा व्यवहार्य हैं;
 - (iii) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति लाम ;
 - (iv) प्रखिल भारतीय सेवाघों के कर्म वारियों के वेतन-क्रम का ढांचा, सेवा की शर्ते तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ ;
 - (V) सशस्त्र सेनामों के कर्मचारियों की सेवा की मतों को ध्यान में रखते हुए उनके बेतन के ढांचे, नकद तथा माल के रूप में मिलने वाले लाभ; ग्रौर मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति लाभ;
 - (Vi) संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों के वेलन के ढांचे तथा सेवा की शर्ते एवं मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति लाभ ; भौर
 - (vii) निम्नतम वेतन के स्तर की जांच करते समय आयोग, केन्द्रीय सरकार के कर्म-चारियों की इस मांग की भी जांच कर सकता है कि न्यूनतम वेतन आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए।
 - 3. भायोग, भ्रपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में, भ्रन्य संबंधित कारणों के साथ साथ, देश की भाषिक स्थित, केद्रीय सरकार के साधनों को तथा उन साधनों पर विकासोमुख भायोजना रक्षा-व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा-व्यवस्था जैस प्रयोजनों के लिए धन की भावण्यकता की एवं राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकार्यों, भावि के विसीय साधनों पर पढ़ने वाले प्रभावों को भी ध्वान में रखेगा।
 - 4. ग्रगर, जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि को वेखते हुए, ग्रायोग द्वारा किये जाने वाले विचार-विमर्श के दौरान श्रंतरिम किस्म को राहत पथ विचार करने की ग्रावश्यकता उपस्थित हो तो ग्रायोग श्रंतरिम किस्म की राहत की मांग पर विचार कर सकता है भौर उस पर ग्रंपनी रिपोर्ट वे सकता है। ग्रंगर ग्रायोग किसी प्रकार की श्रंतरिम राहत दिये जाने की सिफारिश करें तो ग्रायोग इस बाबत भी सुझाब वेगा कि इस प्रकार की राहत किस तारीख से वी जाय।

- 5. घायोग घपने कार्य की विधि स्वयं ही विधित्ति करेगा भीर किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई सलाहकार नियुक्त करने की जरूरत महसस करेगा तो ऐसे सलाहकार नियुक्त करेगा। वह जैसी जरूरी समझेगा वैसी जानकारी मंगवा सकेगा और वैसे साक्ष्य ले सकेगा। घायोग ारा जो जानकारी तथा दस्तावेज और घन्य सहायता मांगी जायगी, वह भारत सरकार के मंज्ञालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। भारत सरकार विश्वास करती है, घायोग को राज्य सरकारों, सेवा संस्थाओं भीर घन्य संबंधित संगठनों घावि द्वारा पूरा सहयोग तथा सहायता वी जायगी।
 - 6. भायोग प्रपनी सिफारिशें, यथा-शक्य शीघ्र प्रस्तुत करेगा। भादेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के र्रेराजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

यह भी भादेश दिया जाता ह कि संकल्प की एक एक प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भ्रन्य सभी संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों भ्रादि को भेजी आया।

पी० गोविन्वम नायर, सचिव ।